संवाद दर्शन

सहयोग राशि-5/-

विक्रम संवत : 2083 | वर्ष : 2026

हिन्दी पाक्षिक

अंक : जून (प्रथम)

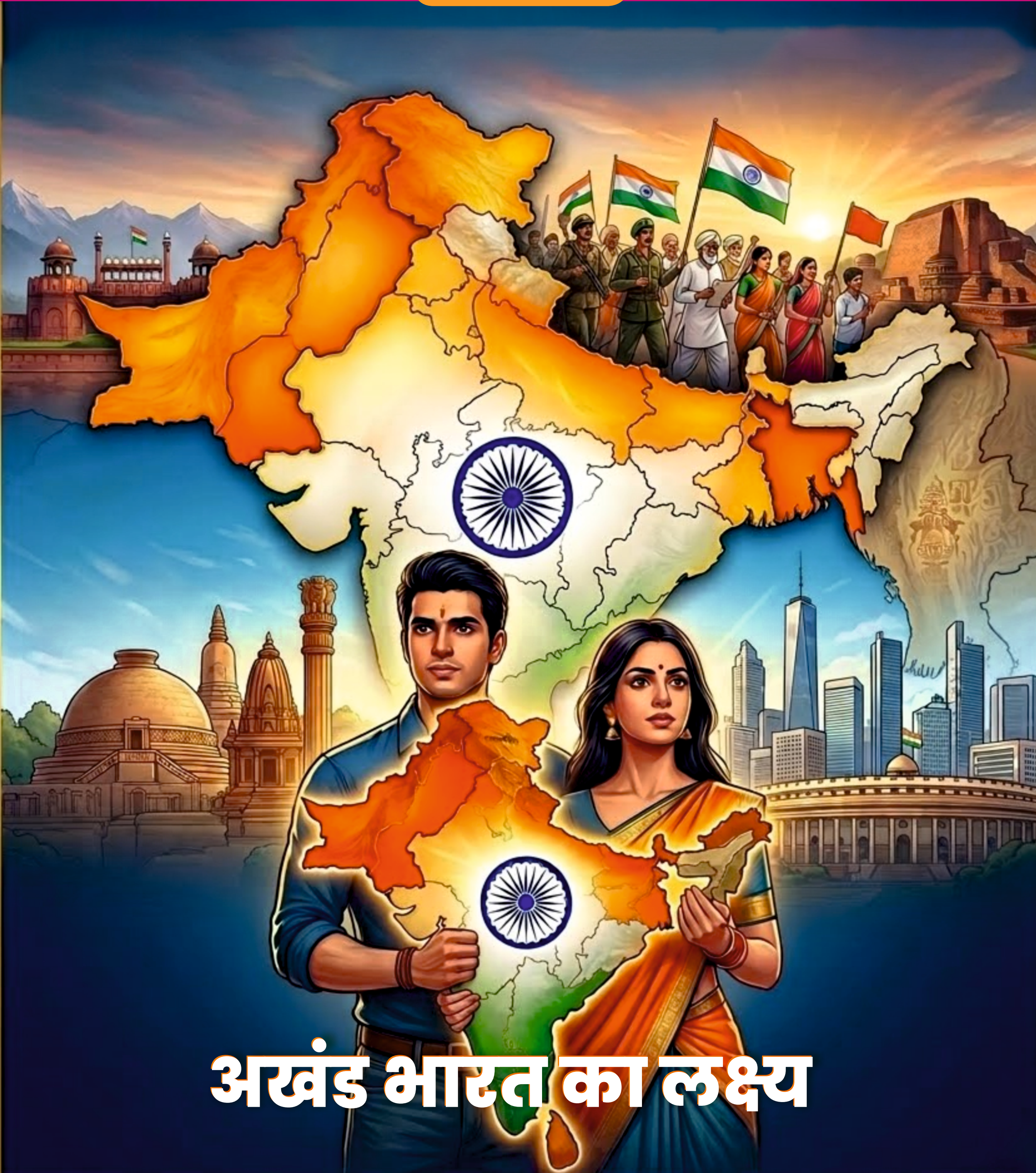

अखंड भारत का लक्ष्य

बुद्धिमान खरगोश और अहंकारी शेर

बहुत समय पहले की बात है, एक विशाल जंगल में श्भासुरकश नाम का एक बहुत ही शक्तिशाली और अहंकारी शेर रहता था। वह अपनी भूख मिटाने के लिए रोजाना बहुत सारे मासूम जानवरों का शिकार करता था। जंगल के सभी जानवर उससे बहुत डरे हुए रहते थे।एक दिन जंगल के सभी जानवरों ने मिलकर एक सभा बुलाई। उन्होंने तय किया कि अगर शेर इसी तरह शिकार करता रहा, तो एक दिन जंगल में कोई जानवर नहीं बचेगा। वे सभी शेर के पास गए और बड़ी विनम्रता से बोले, ष्महाराज, आप जंगल के राजा हैं। हम आपके लिए एक प्रस्ताव लाए हैं। अगर आप रोजाना इतने जानवरों को नहीं मारेंगे, तो हम वादा करते हैं कि हर दिन एक जानवर खुद आपकी गुफा में आपके भोजन के रूप में आ जाएगा।ष्शेर को यह बात पसंद आई क्योंकि अब उसे शिकार के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। उसने चेतावनी दी, ष्ठीक है, लेकिन जिस दिन कोई जानवर नहीं आया, मैं पूरे जंगल को खत्म कर दूँगा।ष्दिन बीतते गए और हर दिन एक जानवर शेर की गुफा में जाने लगा। एक दिन एक छोटे से खरगोश की बारी आई। वह खरगोश बहुत ही बुद्धिमान और चतुर था। वह मरना नहीं चाहता था, इसलिए उसने अपनी जान बचाने के लिए एक योजना सोची। वह जानबूझकर शेर की गुफा में बहुत देर से पहुँचा।इधर शेर भूख के मारे आग–बबूला हो रहा था। जब उसने एक छोटे से खरगोश को अपनी ओर आते देखा, तो वह दहाड़कर बोला, ष्एक तो तुम इतने छोटे हो कि मेरी भूख भी नहीं मिटेगी, ऊपर से तुम इतनी देर से आए हो! मैं अभी जाकर सभी जानवरों को मार डालूँगा।ष्खरगोश ने हाथ जोड़कर कहा, ष्महाराज! इसमें मेरी या बाकी जानवरों की कोई गलती नहीं है। मैं तो समय पर ही चला था और मेरे साथ पाँच और खरगोश थे। लेकिन रास्ते में हमें एक दूसरा शेर मिला। उसने दावा किया कि वह इस जंगल का असली राजा है और उसने बाकी खरगोशों को खा लिया। मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर आपको यह बताने आया हूँ।ष्यह सुनकर भासुरक गुस्से से पागल हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, ष्इस जंगल में मेरे अलावा दूसरा राजा कौन है? मुझे अभी उसके पास ले चलो, मैं उसे खत्म कर दूँगा।ष्नन्हा खरगोश शेर को एक गहरे कुएँ के पास ले गया और बोला, ष्महाराज, वह इसी किले (कुएँ) में छिपा हुआ है।ष शेर ने कुएँ के अंदर झाँका, तो उसे पानी में अपनी ही परछाई दिखाई दी। गुस्से में पागल शेर ने अपनी परछाई को ही दूसरा शेर समझ लिया। वह जोर से दहाड़ा और कुएँ से उसकी अपनी ही दहाड़ की गूँज सुनाई दी।भासुरक को लगा कि दूसरा शेर उसे चुनौती दे रहा है। बिना सोचे–समझे, वह कुएँ में कूद पड़ा और पानी में डूबकर मर गया। नन्हे खरगोश ने अपनी बुद्धिमानी से न केवल अपनी जान बचाई, बल्कि पूरे जंगल को उस क्रूर शेर से हमेशा के लिए आजाद करा दिया।

संवाद दर्शन
हिन्दी पाक्षिक

सलाहकार संपादक
देवेन्द्र मिश्र

संपादक
संजीव कुमार

प्रकाशक एवं मुद्रक
बिमल कुमार जैन

प्रिंटर्स
लोकवाणी प्रिंटिंग प्रेस,
शशि काम्प्लेक्स,
नाला रोड, कदमकुआँ
पटना

पता
विश्व संवाद केंद्र
104-105, सूर्या अपार्टमेंट,
फ्रेजर रोड, पटना - 800 001
संपर्क = 0612 2216048

ई-मेल- vskpatna@gmail.com
vskbihar@gmail.com
वेबसाइट- www.vskbihar.com

अनुक्रमणिका

पाठकों के नाम पत्र

प्रिय पाठक,
सादर नमस्कार।

आशा है आप स्वस्थ एवं सानंद होंगे। विदित हो कि 'संवाद दर्शन' पत्रिका राष्ट्र तथा प्रदेश की घटनाओं और महत्वपूर्ण बिन्दुओं को आधार बनाकर प्रकाशित हो रही है। आपका स्नेह हमेशा प्राप्त होता रहता है। पत्रिका द्वारा सदस्यों/ पाठकों के नाम, पता, दूरभाष तथा ई–मेल में सुधार के लिए योजना चलायी जा रही है। संवाद दर्शन परिवार आशा करता है कि पत्रिका आप तक पहुंच रही होगी। यदि नहीं पहुंच रही है तो आप हमारे दूरभाष पर संपर्क कर या हमारे पते पर पत्र लिखकर अपने पता का सुधार करवा सकते हैं।
शेष शुभ!

तकनीक से ताल

21वीं सदी में जब इंटरनेट आधारित माध्यमों की सघनता बढ़ने लगी और मनोरंजन के नए—नए आयाम विकसित होने लगे, तो पिछली सदी के विगत कई दशकों से लोगों के लिए सूचना और मनोरंजन का प्रमुख साधन रहे आकाशवाणी पीछे छूटने लगा था और संभवतः लगने लगा था कि आने वाले कुछ वर्षों में आकाशवाणी की प्रासंगिकता और भी संकीर्ण हो जाएगी। लेकिन, तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 'मन की बात' कार्यक्रम से आकाशवाणी को एक प्रकार से नई संजीवनी प्रदान कर दिया। प्रधानमंत्री की इस पहल से पता चलता है कि संस्थाओं की प्रासंगिकता बनाए रखना और जनकल्याण के लिए उनको सही दिशा की ओर निरंतर प्रगतिशील रखना, एक द्रष्टा ही कर सकता है।

नरेंद्र मोदी से पहले देश के प्रधानमंत्री भारत से बाहर जाते थे तो निजी चैनलों का एक पूरा काफिला सरकारी खर्चे पर प्रधानमंत्री के साथ जाता था। मोदी ने अनावश्यक भीड़ बढ़ाने के स्थान पर दूरदर्शन को अपनी बात प्रसारित करने का माध्यम चुना। अब हम पाते हैं कि प्रधानमंत्री के किसी कार्यक्रम का निजी चैनलों द्वारा 'दूरदर्शन के सौजन्य से' प्रसारण किया जाता है। यह आकाशवाणी के बाद दूरदर्शन की प्रासंगिकता बनाए रखने का दूसरा उदाहरण मोदी ने प्रस्तुत किया।

ऑनलाइन डिग्री पाठ्यक्रम और स्वयं पोर्टल से छोटे—छोटे कोर्स घर बैठे पूरा करने की सुविधा भी मोदी सरकार की उपलब्धियों में से है। सरकारी व्यवस्था में बहुत से कार्य अनवरत आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन, उन कार्यों में प्रधानमंत्री मोदी की स्वयं सक्रिय सहभागिता एक उम्मीद व विश्वास उत्पन्न करती है। डेढ़ अरब की आबादी वाले देश में

इंटरनेट आधारित शिक्षा व्यवस्था को सुदूर गांवों तक सुलभ बना देना, यह साधारण बात नहीं है। शिक्षा के अतिरिक्त स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी प्रधानमंत्री ने तकनीक के महत्व को न केवल समझा है, बल्कि यह सुनिश्चित किया है कि इसका लाभ आम नागरिक को मिले। भारत के 244 से अधिक कैंसर अस्पतालों को नेशनल कैंसर ग्रिड (NCG) के पोर्टल से जोड़ा गया है। इसकी स्थापना 2012 में हुई थी, तथापि इसके काम में तेजी मोदी कार्यकाल के दौरान ही आई, आंकड़े साक्षी हैं। इसमें कोई भी कैंसर रोगी घर बैठे अपने रिपोर्ट अपलोड कर देश के नामी कैंसर विशेषज्ञ से उपचार संबंधी परामर्श ले सकता है। स्पष्ट है कि नेशनल कैंसर ग्रिड की सुविधा मिलने से कैंसर रोगियों को छोटी–मोटी बात के लिए अस्पतालों के चक्कर काटने से राहत मिली है।

याद होगा देश के पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम ने इंटरनेट आधारित भुगतान व्यवस्था की जटिलता बताते हुए तंज कसा था कि सब्जी बेचने वाले अथवा रेहड़ी/खोंमचा लगाने वाले ऑनलाइन पेमेंट कैसे लेंगे? क्या सरकार सब्जी मंडी में वाईफाई लगवाएगी? लेकिन, 2016 मोदी जी के संकल्प के साथ शुरू हुआ डिजिटल इंडियाअभियान का परिणाम है कि आज ₹1 की भी खरीदारी अगर कोई फुटपाथ पर खोमचे वाले से करता है, तो उसका भी भुगतान लेने के लिए वह गर्व के साथ अपना क्यूआर कोड ग्राहक के समक्ष रख देता है।

नरेंद्र मोदी एक लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं और जगजाहिर है कि उनके साथ फोटो खींचने और सेल्फी लेने की होड़ मची रहती है। मोदी जी भी इस बात को समझते हैं। कई बार होता है कि किसी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के साथ किसी का फोटो आ तो गया लेकिन उसे मिल नहीं पाता है। इतनी मामूली सी लगने वाली बात को भी प्रधानमंत्री ने समझा और नमो ऐप में ऐसी व्यवस्था बनवा दी कि अगर भारत के किसी भी व्यक्ति का फोटो मोदी जी के साथ है, तो उस ऐप पर अपना कोई भी फोटो जैसे ही अपलोड करेगा, तो वे सारे फोटो उसे एक साथ उपलब्ध हो जाएंगे जिसमें वह और प्रधानमंत्री किसी एक फ्रेम में हों।

कुछ साल पहले तक भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली एनएफडीसी मृतप्राय हो गई थी। लेकिन, जिस प्रकार से भारत में होने वाली सिनेमा गतिविधियों के लिए एनएफएआई, सीएफएसआई, एफडी आदि अन्य संस्थाओं को मर्ज कर एनएफडीसी को सशक्त किया गया और आज दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी सिनेमाई एजेंसी के रूप में एनएफडीसी कार्य कर रही है, तो इसके पीछे भी प्रधानमंत्री का वह विजन कम कर रहा है। इसी वर्ष 1 में से लेकर 4 में तक मुंबई के जिओ सेंटर में प्रथम वेब सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया था। विश्व भर के 90 देशों से एक लाख से अधिक आमंत्रित अतिथि आए थे। प्रसिद्ध अभिनेता शाहरुख खान को मंच से कहना पड़ा इतने सालों के करियर में सरकार द्वारा प्रायोजित सिनेमा और मनोरंजन का इतना व्यापक कोई कार्यक्रम उन्होंने नहीं देखा था।

यह सत्य है कि हर प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान कोई न कोई तकनीकी परिवर्तन हुआ। लेकिन, प्रद्यौगिकी व इंटरनेट को लेकर ऐसा आग्रही प्रधानमंत्री शायद ही भारत के देखा हो। यह कहना कभी अतिशयोक्ति नहीं होगा कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के पहले किसी भी नई तकनीक के आने पर वह देश के मुट्ठीभर कुलीन जनों के लिए आरक्षित रहती थी। याद कीजिए, इसी देश में टेलीफोन रखाना लग्जरी होता था। लेकिन, आज जो 5जी सर्विस किसी अरबपति के पास है, वही 5जी सर्विस एक रेहड़ी वाले के पास है। इसीलिए आलेख के शुरू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द्रष्टा की संज्ञा दी गई है। यह अकारण नहीं है।

बदला 'प्रतिरक्षा' का अर्थ

भारत को अपनी जन्म–भूमि, कर्मभूमि, मातृ–भूमि, पितृ–भूमि एवं पुण्य भूमि मानने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए इसकी आंतरिक व बाह्य सुरक्षा सर्वोपरी है। इस दृष्टि से भारत की आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा में आरएसएस की भूमिका का विश्लेषण केवल उसके कार्यों की सूची तक सीमित नहीं है। आरएसएस भारत की सुरक्षा, गौरव एवं सम्मान की रक्षा मामलों में कैसे सहभागी है, इसे जानने लिए उसकी पूरी वैचारिकी और संगठनात्मक पृष्ठभूमि और संरचना को समझना होगा। संघ की दृष्टि में राष्ट्रीय सुरक्षा और सामर्थ्य के केंद्र में प्रत्येक भारतवंशी हैं। इस प्रकार आरएसएस के लिए, आंतरिक सुरक्षा केवल पुलिस, सेना और खुफिया एजेंसियों का विषय नहीं है, बल्कि यह एक सांस्कृतिक और सामाजिक लक्ष्य है, जिसे एक विशेष प्रकार के समाज और व्यक्ति का निर्माण करके प्राप्त किया जा सकता है।

आधुनिक राष्ट्र–राज्य की अवधारणा में, आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखना राज्य का प्राथमिक उत्तरदायित्व माना जाता है। आंतरिक सुरक्षा का तात्पर्य केवल कानून और व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें राष्ट्र की सीमाओं के भीतर शांति, सांप्रदायिक सद्भाव और संप्रभुता की रक्षा करना भी शामिल है। पश्चिमी देशों से उधार में लिए गए राष्ट्र राज्य के इस परिकल्पना के भारत में भयावह परिणाम हुए हैं। अंग्रेजों से राजनीतिक आजादी प्राप्त करने के लिए भारत को विभाजित किया गया। इसकी पीड़ा से भारत के लोग आज भी बेचैन है। औपनिवेशिक शक्तियों द्वारा आरोपित इस सिद्धांत को आजादी के बाद भी काले अंग्रेजों ने भारतीयों पर आरोपित कर दिया।

भारत जैसा विशाल देश जहां प्राचीनकाल से एकात्मता के विविधता पूर्ण भाव बोध से युक्त लोकतंत्रिक मूल्यों को जीने की परंपरा रही है, वहां तंत्र की औपनिवेशिक मानसिकता के कारण सामाजिक–आर्थिक असमानताओं, क्षेत्रीय संघर्षों, आतंकवाद और सांप्रदायिक तनावों जैसी समस्याएं गहराती चली गयीं। इससे आंतरिक सुरक्षा की समस्या जटिल होती चली गयी। इस जटिल वातावरण में आरएसएस महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहा हैं।

कांग्रेस के 1922 के खिलाफत आंदोलन में शामिल होने के बाद भारत की राजनीति में तुष्टिकरण का जहर प्रवेश कर चुका था। ऐसी परिस्थिति में 27 सितंबर, 1925 को विजयादशमी के दिन नागपुर में डा. केशव बलराम हेडगेवार ने आरएसएस की स्थापना की थी। अपनी स्थापना के बाद से आरएसएस भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ते हुए दुनिया के सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठन के रूप में विकसित हुआ है। इसकी व्यापक जमीनी उपस्थिति, अनुशासित कैडरों का बड़ा नेटवर्क और गहरी वैचारिक प्रतिबद्धता ने इसे एक अद्वितीय गैर–राजनीतिक संगठन बनाया। इसकी गतिविधियां सीधे तौर पर भारत के सामाजिक–सांस्कृतिक और राजनीतिक ताने–बाने को प्रभावित किया। स्थापना के बाद से बिना रूके संघ का कार्य आगे बढ़ता गया और अब यह संगठन विश्व का सबसे बड़ा गैरसरकारी स्वयंसेवी संगठन है जो अपने देश भारत की आंतरिक सुरक्षा व बाह्य सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में इसके प्रयास का उदाहरण नहीं दिखता।

20वीं सदी का शुरुआती दशक भारत के लिए उथल–पुथल से भरा था। ब्रिटिश शासन के अत्याचार, मैकाले की शिक्षा के कारण सामाजिक बिखराव और राष्ट्रीय गौरव में कमी के माहौल में, डा. हेडगेवार ने महसूस किया कि भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए हिंदू समाज को एकजुट और अनुशासित करना आवश्यक है । डा. हेडगेवार स्वयं एक स्वतंत्रता सेनानी थे और अनुशीलन समिति जैसे क्रांतिकारी संगठनों से जुड़े थे, और असहयोग आंदोलन के दौरान जेल भी गए थे । हालांकि, महात्मा गांधी के नेतृत्व वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीतियों से उनका वैचारिक मतभेद था। उनका मानना था कि कांग्रेस का आंदोलन केवल राजनीतिक स्वतंत्रता पर केंद्रित था, न कि राष्ट्र के चरित्र निर्माण पर। विशेष रूप से, कांग्रेस का 'अहिंसा' का सिद्धांत और 'खिलाफत आंदोलन' के प्रति समर्थन, हेडगेवार की दृष्टि में, हिंदू समाज और भारत के हितों को कमजोर कर रहा था। डा. हेडगेवार का कांग्रेस से यह मोहभंग हो गया और उन्होंने कुछ युवाओं को जोड़कर इस संगठन की स्थापना की।

एक सुरक्षा प्रतिमान

संघ की वैचारिक नींव का विश्लेषण यह स्पष्ट करता है कि 'हिंदू राष्ट्र' की अवधारणा केवल एक राजनीतिक या सांस्कृतिक लक्ष्य नहीं है, बल्कि इसे भारत की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के अंतिम गारंटर के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इस तर्क के अनुसार, एक राष्ट्र जो आंतरिक रूप से एक ही सांस्कृतिक पहचान (हिंदुत्व) से एकीकृत है, वह बाहरी खतरों और आंतरिक विखंडन के विरुद्ध स्वाभाविक रूप से अधिक सुरक्षित और लचीला होता है।

संघ का आधिकारिक ध्येय 'हिंदू समाज को संगठित करना,' 'हिंदू धर्म की रक्षा करना,' और राष्ट्र को 'परम वैभव के शिखर' तक ले जाना है। यह भव्य रणनीतिक उद्देश्य स्थापित करता है। इसकी विचारधारा को सभी भारतीय लोगों के लिए 'एकल, एकीकृत हिंदू पहचान' को बढ़ावा देने के रूप में वर्णित किया गया है और यह हिंदुत्व की व्यापक धारणा पर आधारित है। इसमें मत–सम्प्रदाय, मजहब और पूजा पद्धति का कोई स्थान नहीं बल्कि मातृभूमि के संतान के रूप में सबकी पहचान का आग्रह केंद्रीय भाव है। यह

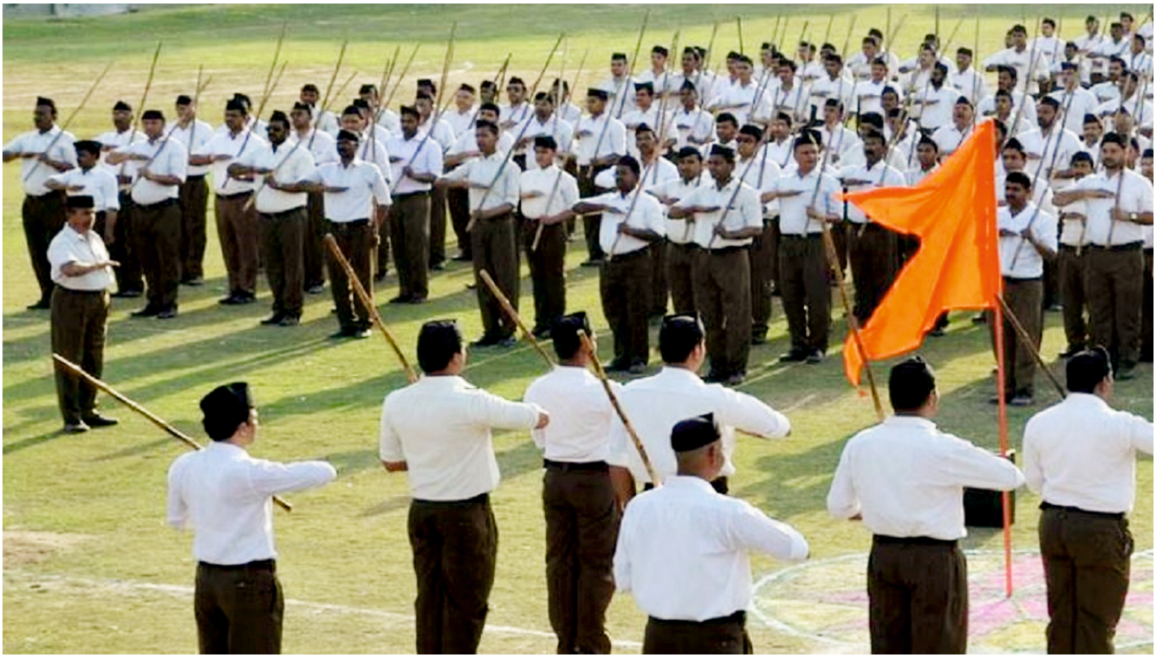

इसके एकता प्रतिमान की विशिष्ट प्रकृति को उजागर करता है।

संगठन की स्थापना 1925 में केशव बलिराम हेडगेवार द्वारा सांप्रदायिक तनाव के दौर में हिंदू राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक हितों की रक्षा के लिए एक 'अनुशासित कैडर' बनाने के लिए की गई थी । हेडगेवार का मानना था कि हिंदुओं को एक एकजुट समुदाय बनाने के लिए संगठित होने की आवश्यकता है । यह ऐतिहासिक संदर्भ प्रदान करता है। संघ की कल्पना संगठन के माध्यम से ऐसी आंतरिक सुरक्षा के खतरे के स्थायी समाधान देना है। इसके पीछे किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं।

संघ स्वयं को एक सांस्कृतिक, न कि राजनीतिक, संगठन के रूप में प्रस्तुत करता है। यह वैचारिक पृष्ठभूमि आंतरिक सुरक्षा की पारंपरिक परिभाषा को बदल देता है। यह पुलिसिंग और खुफिया जानकारी के पारंपरिक राज्य–केंद्रित मॉडल से आगे बढ़कर एक समाज–केंद्रित मॉडल की ओर जाता है, जहां सुरक्षा सांस्कृतिक और वैचारिक एकता के माध्यम से प्राप्त की जाती है। इस दृष्टिकोण में, प्राथमिक आंतरिक खतरा केवल आतंकवाद या अपराध नहीं है, बल्कि सामाजिक विखंडन, धार्मिक रूपांतरण और एक विलक्षण राष्ट्रीय–सांस्कृतिक पहचान का कमजोर होना है। संघ का घोषित लक्ष्य 'हिंदू समाज को संगठित करना' है। संघ के आलोचकों का आरोप है कि इसकी स्थापना सांप्रदायिक तनाव और हिंदू समाज में एक कथित कमजोरी की प्रतिक्रिया थी।

आरएसएस के वर्तमान सरसंघचालक डा. मोहन भागवत कहते हैं कि सुरक्षा समाज से शुरू होती है, केवल राज्य से नहीं, और वे एक 'खंडित समाज' के खिलाफ चेतावनी देते हैं। इसलिए, हिंदुत्व की भावभूमि पर समाज को 'संगठित' और 'एकीकृत' करने का कार्य, संघ के लिए, राष्ट्र को भीतर से सुरक्षित करने का एक प्राथमिक कार्य है। आंतरिक असुरक्षा का समाधान केवल बेहतर कानून नहीं, बल्कि एक अधिक सजातीय समाज है। इसके

गहरे निहितार्थ हैं, क्योंकि यह तार्किक रूप से विविधता और अल्पसंख्यक अधिकारों के नाम पर होने वाली निकृष्ट राजनीति के विकृत चेहरे को भी उजागर करता है।

'स्वयंसेवक' रक्षा की पहली इकाई

संघ की कार्यप्रणाली का मूल 'शाखा' है, जो एक विशेष प्रकार के नागरिक स्वयंसेवक के निर्माण की मौलिक इकाई है। यह स्वयंसेवक उस अनुशासन, चरित्र और वैचारिक प्रतिबद्धता का प्रतीक है जिसे राष्ट्रीय रक्षा के लिए आवश्यक माना जाता है। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक रूप से स्वस्थ एवं सक्षम मनुष्य जो अपने देश, समाज, संस्कृति के प्रति समर्पित हो वही स्वयंसेवक की श्रेणी में आता है। संघ परिवार का विशाल पारिस्थितिकी तंत्र यह दर्शाता है कि संघ अपनी वैचारिक पहुंच को भारतीय जीवन के हर पहलू तक कैसे बढ़ाता है। यह नेटवर्क गैर–सरकारी संगठनों का एक यादृच्छिक संग्रह नहीं है, बल्कि एक पूर्ण समझदारी के साथ संरचित 'संगठनों का परिवार' है जिसे राष्ट्रीय विमर्श को आकार देने और विशिष्ट जनसांख्यिकी को संगठित करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे कई मोर्चों से आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके।

संघ परिवार संघ द्वारा निर्देशित 40 से अधिक संबद्ध संगठनों का एक नेटवर्क है, जो राजनीति (भाजपा), धर्म (विहिप), श्रम (बीएमएस), शिक्षा (विद्या भारती), और छात्रों (एबीवीपी) जैसे विविध क्षेत्रों में काम करता है । प्रमुख कर्मी, जो अक्सर पूर्णकालिक संघ कार्यकर्ता होते है, उन्हें प्रचारक कहा जाता हैं। ये सहयोगियों का नेतृत्व करने के लिए प्रतिनियुक्त किए जाते हैं, जिससे वैचारिक सुसंगतता और केंद्रीत दिशा सुनिश्चित होती है। यह संरचना संघ को जीवन के विविध क्षेत्रों में विस्तार के लिए अनुकूल वातावरण बनाता है जिससे उसके व्यापक उद्देश्य की प्राप्ति में सहयोग मिलता है। वैसे तो आरएसएस का काम केवल शाखा लगाना होता है लेकिन उस शाखा में प्रशिक्षित स्वयंसेवक अपनी रूचि और क्षमता के

अनुसार विशिष्ट गतिविधियों में संलग्न होकर समाज और राष्ट्र नवनिर्माण में अपना योगदान करते हैं।

स्कूल चलाने का कार्य विद्या भारती और एकल विद्यालय संगठन करता है। उसी प्रकार विद्यार्थियों में ज्ञान, शील, एकता और अनुशासन के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम से हजारों स्वयंसेवक कार्य कर रहे हैं। सामाजिक सेवाएं प्रदान करने की इच्छा रखने वाले सेवा भारती से जुड़कर कार्य कर रहे है। इसी प्रकार चुनावी राजनीति करने वाले भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं। संघ की स्थापना के बाद जैसे–जैसे कार्य की आवश्यकता महसूस हुई वैसे–वैसे विविध संगठन बनते चले गए। सबसे पहले वर्ष 1949 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना हुई। इसके बाद 1952 में भारतीय राष्ट्रीय जनसंघ और 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी। धार्मिक–सांस्कृतिक संगठन विश्व हिंदू परिषद की 1964 में स्थापना हुई। 1984 में बजरंग दल बना। सामाजिक सेवा व लोककल्याण के लिए 1979 में सेवा भारती की स्थापना हुई। आवश्यकतानुसार कार्य विस्तार के लिए आरएसएस ने 40 से अधिक विशाल संगठनों का निर्माण किया।

अखंड भारत का लक्ष्य

भारत की आजादी के शताब्दी महोत्सव तक जिस नवभारत की परिकल्पना है उसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, वर्मा आदि भी शामिल हैं। निःसंदेह इस परिकल्पना को असंभव कह कर खारिज किया जा सकता है लेकिन, कल्पना ही हकीकत में बदलते रहे हैं।

अखंड भारत को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डा. मोहन भागवत के विचार स्पष्ट हैं। वे समय–समय पर सार्वजनकि सभाओं में भी इस विषय में वे अपना विचार स्पष्टता के साथ रखते रहे है। वैसे, आरएसएस अपने स्थापना काल से ही अखंड भारत की बात करता रहा है। यही कारण है कि 14 अगस्त को वह 'अखंड भारत संकल्प दिवस' के रूप में मनाता है। स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पूर्व प्रतिवर्ष संघ के स्वयंसेवक अखंड भारत का संकल्प लेते हैं।

अब प्रश्न यह उठता है कि है कि क्या अखंड भारत कभी हकीकत हो सकता है या फिर यह एक भावनात्मक अभिव्यक्ति मात्र है। समारोह में दिए गए बयानों तक और संकल्प की औपचारिकता के अलावा भी इसमें कुछ ठोस तथ्य हैं।

सरसंघचालक डा.मोहन भागवत ने इस वर्ष भी पाकिस्तान को भारत के घर के एक कमरे की तरह बता दिया और कहा कि इस पर फिर से डेरा डालना है। उन्होंने कहा कि हमारा एक कमरा किसी ने हथिया लिया। कल मुझे उसे वापस लेकर वहां फिर से अपना डेरा डालना है, वह पाकिस्तान नहीं अविभाजित भारत है। उन्होंने वर्ष 2023 में दिल्ली में एक बड़े संवाद कार्यक्रम में कहा था कि परिस्थितियां अब ऐसी करवट ले रही हैं, जो भारत से अलग हुए हैं, उन्हें लगने लगा है कि गलती हो गई, हमें फिर से भारत में होना चाहिए।

डा. मोहन भागवत के पूर्ववर्ती सरसंघचालक कुसी सुदर्शन भी दृढ़ता के साथ दावा करते थे कि कुछ समय लगेगा लेकिन भारत अखंड होगा क्योंकि औपनिवेशिक शक्तियों के षड्यंत्र के कारण भारत का जो विभाजन हुआ है वह अप्राकृतिक है। प्रकृति इस गलती को सुधार देगी। तीन साल पहले भागवत ने एक तरह से टाइमलाइन भी दी थी। तब उन्होंने कहा था कि 20–25 साल में तो भारत अखंड भारत बन जाएगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे तो 15 साल में भी ऐसा हो सकता है। ऐसा दावा करते हुए डा. मोहन भागवत के दिमाग में भारत की आजादी के शताब्दी वर्ष की योजना की रूप रेखा तो नहीं चल रही?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह घोषणा की है कि यह भारत का अमृतकाल है। जब हम भारत की आजादी की शताब्दी महोत्सव मनायेंगे तब भारत विश्व में विकसित देशों की कतार में खड़ा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस के

सरसंघचालक डा. मोहन भागवत दोनों का चिंतन दिशा एक ही लगने लगता है। दोनों का लक्ष्य भी एक ही लगने लगता है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनशक्ति को संगठित कर उसे एक दिशा में लगा देना ताकि भारत का सामर्थ्य पूरे विश्व में स्पष्ट दिखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में भारत के 140 करोड़ बंधुओं को एकभाव से सम्बोधित करते हैं। वहीं डा. मोहन भागवत आरएसएस को समाज का संगठन कहते हैं यानी पूरे समाज का संगठन, समाज में कुछ लोगों का संगठन नहीं।

भारत की नई संसद के अंदर अखंड भारत का भित्ति चित्र भी बना हुआ है। जब नई संसद का उद्घाटन हुआ और यह सामने आया तो पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश ने इस पर आपत्ति जताई। तब भारत सरकार ने साफ किया कि यह सम्राट अशोक का साम्राज्य है न कि अखंड भारत का नक्शा। यह भी कहा कि भारत सभी पड़ोसी देशों की संप्रभुता का सम्मान करता है। 2014 से पहले जब तक भाजपा केंद्र सरकार में नहीं थी, तब तक पार्टी के कुछ नेताओं के बयानों में कभी–कभी अखंड भारत आता था। लेकिन केंद्र सरकार में आने के बाद भाजपा के सीनियर नेताओं के बयान पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर तक ही सीमित हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी लगातार पीओके की बात करते रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी और उससे पहले भी उन्होंने कई मौकों पर कहा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लोग खुद ही आएंगे और कहेंगे कि हमें भारत का हिस्सा बनना है। रक्षामंत्री का यह बयान संघ की दूरगामी रणनीति की ओर संकेत करता है। आरएसएस की नीति है कि पूजा पद्धति बदलने से पूर्वज नहीं बदलते। हमारे पूर्वज एक हैं अतः हम फिर से एक हो सकते हैं। इस्लाम के नाम पर अलग देश बनने के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश में अशांति और हिंसा का वातावरण है जिससे वहां के लोग त्रस्त हैं। ऐसे में वहां के लोगों की सोच में बदलाव आने लगे है। इस बदलाव का उपयोग कर अखंड भारत का सपना साकार हो सकता है।

पीओके को लेकर राजनीति हमेशा होती रही है। इसलिए जब पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया तो देश में इस तरह का माहौल बन गया कि अब पीओके को भारत लेकर ही रहेगा। जब चार दिन में सीजफायर हो गया तो लोगों की इस उम्मीद की तपिश से राजनीतिक हलके में हलचल शुरू हो गया। बीजेपी के विरोधी तंज कसने लगे। ये सवाल भी उठने लगे कि जब आर्म्ड फोर्सेस ने ऑपरेशन लॉन्च ही कर दिया था तो फिर पीओके को लेने तक ऑपरेशन क्यों नहीं चलाया गया? विपक्ष की तरफ से भी ये सवाल उठाए गए और इसलिए भी ये सवाल उठे क्योंकि भाजपा के नेता हमेशा अपने भाषणों में पीओके को लेने का जिक्र करते रहे हैं।जब संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई तो रक्षा मंत्री को इसका जवाब देना पड़ा। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद टेरिटरी कब्जा करना नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर का मकसद था आतंक की नर्सरी नष्ट करना। ऑपरेशन उन मासूम परिवारों को न्याय दिलाने के लिए लॉन्च किया गया था, जिन्होंने पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद में अपने प्रियजनों को खोया। ऑपरेशन का राजनीतिक और सैन्य मकसद यह था कि प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे पाकिस्तान को सजा दी जाए। हमारा मकसद युद्ध छेड़ना नहीं था, बल्कि फोर्स की कार्रवाई से दुश्मन को झुकने के लिए मजबूर करना था। हालांकि उनके इस बयान के बाद भी कई विपक्षी नेताओं ने सवाल उठाए और कहा कि क्या भाजपा अब पीओके को भारत में मिलाने की अपनी बात से पलट गई है? सौ वर्षों के सतत प्रयास से संघ विचार परिवार ने जिस प्रकार का सामाजिक, राजनीतिक, बौद्धिक आरै सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण किया है उसमें अखंड भारत का एजेंडा और दृढ़ होगा।

नव भारत में विमर्श सुधार

विमर्श समाज के सामूहिक चेतना का दर्पण होता है। विमर्श का अर्थ केवल चर्चा या संवाद करना नहीं होता बल्कि यह सम्पूर्ण समाज की सोच एवं दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है। जहां एक ओर सकारात्मक विमर्श समाज के विकास एवं भविष्य की दिशा निर्धारित करने मे सहायक होता है, वहीं दूसरी ओर नकारात्मक विमर्श समाज के उत्थान में अवरोध पैदा करता है और उसे दिशाहीन बना देता है।

भारतीय सभ्यता में सकारात्मक विमर्श की परंपरा आदि काल से ही विद्यमान रही है और यही कारण है की जो विमर्श भारतीय मूल की अवहेलना करता है वो नकारात्मक, विभाजनकारी एवं पूर्वाग्रहों से ग्रसित होते हैं। भारत में वर्षों की गुलामी एवं उपनिवेशवाद के प्रभाव के कारण योजनाबद्ध तरीके से एक ऐसे ही नकारात्मक विमर्श का निर्माण किया जाता है जिसमे भारतीय सभ्यता, संस्कृति एवं ज्ञान को ओछा एवं पश्चिमी मूल्यों को श्रेष्ठ बताया गया। आजादी के बाद इस मानसिकता को खंडित करने एवं सकारात्मक विमर्शों को स्थापित करने का एक सुनहरा मौका था मगर राजनीतिक इच्छाशक्ति के अभाव एवं वामपंथियों के प्रभाव के कारण यह तब भी संभव नहीं हो सका।

आजादी के पश्चात पश्चिमी देशों ने भारत समेत कई एशियाई देशों को 'वाइट मेंस बर्डेन' की संज्ञा दी और हमने 'इंग्लिश मॉडल ऑफ़ डेवलपमेंट' को ही विकास का एक मात्र विकल्प मानना शुरू कर दिया। इस तरह 1947 में भारत राजनीतिक रूप से तो आज़ाद हुआ मानसिक, आर्थिक और तंत्र के दृष्टि से पश्चिमी देशों के अधीन ही रह गया।

बहरहाल पिछले एक दशक से भारत में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक वातावरण में व्यापक परिवर्तन होना शुरू हो गया है। जिसकी वजह से न सिर्फ भारत में बल्कि वैश्विक पटल पर भी भारत से जुड़े विमर्शों में सुधार दिखने लगे है। पिछले एक दशक में भारत अपने व्यवहार से पूरे विश्व को यह यकीन दिलाने में कामयाब हो गया है की 21वीं सदी का यह भारत केवल अपने अतीत पर गर्व करने वाला देश नहीं है बल्कि वह आज की चुनौतियों का सामना करने में भी उतना ही सक्षम है।

यही नया भारत की अवधारणा है। नया भारत की यह अवधारणा केवल एक कल्पना मात्र नहीं है बल्कि यह एक संकल्प है जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त, 2025 को लाल किले के प्राचीर से किया। अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री ने देश के सामने 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का पूरा रोडमैप प्रस्तुत किया जिसमे भारत को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना, हर भारतीय में राष्ट्रवादी चेतना का विकास करना एवं वासुधैव कुटुम्बकम की भावना से पुरे विश्व का मार्गदर्शन करने जैसा लक्ष्य निर्धारित किया गया।

भारत की वैश्विक भूमिका

एक दशक से पूर्व जिस भारत को वैश्विक स्तर पर महज एक फॉलोवर के रूप में देखा जाता था। वह देश आज हर क्षेत्र में विश्व का पथप्रदर्शन कर रहा है। जहां एक ओर कई पक्षिमी देश इंडो–पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता, लोकतंत्र की मजबूती, सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करना तथा जलवायु परिवर्तन जैसे तमाम अहम विश्वस्तरीय मुद्दों पे बैकफुट पर दिखाई दे रहा है वहीं भारत इन मुद्दों पर विश्व की दिशा तय करने में अहम् भूनिका निभा रहा है। भारत ने जहाँ एक तरफ कोरोना महामारी के वक्त विश्व के कई विकसित देशों को मुफ्त दवाईयाँ उपलब्ध करा कर वसुदेवकुटुम्बकम का पाठ पढ़ाया वहीं दूसरी ओर आतंकवाद जैसे मुद्दों पर जीरो टॉलरेंस का रुख अपना कर 'ऑपरेशन सिन्दूर' जैसे बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। 'ऑपरेशन सिन्दूर' जैसे साहसिक कदमों से भारत ने पुरे विश्व को अपने सामर्थ का परिचय देते हुए यह स्पस्ट कर दिया की नया भारत की तरफ आँख उठा कर देखने वाले देशों के खिलाफ अब भारत केवल डायलॉग नहीं करेगा बल्कि एक्शन लेगा। नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भी भारत हवा और सौर्य से सबसे ज्यादा बिजलीउत्पान्न करने वाला विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। नोवी इंस्टिट्यूट द्वारा प्रकाशित एशिया पावरफुल इंडेक्स के रिपोर्ट के मुताबिक भारत जापान को पछाड़ कर एशिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बन चूका है। वैश्विक विषयों पर भारत द्वारा लिए गए यह सभी साहसिक कदम यह दर्शाते है कि भारत पुनः विश्व गुरु बनने की ओर तेजी से अग्रसर है।

मुसलमानों का तुष्टिकरण

वैश्विक मुद्दों के साथ–साथ अपने आतंरिक मामलों में भी भारत में कई कड़े निर्णय लिए जा रहे है जो भारत को नया भारत बनाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। पिछली दशक से पूर्व भारत में मुसलमानो को केवल एक वोट बैंक के रूप में देखा जाता था। नजीतन मुसलमानों द्वारा दिए गए वोट कभी उनकी शैक्षणिक, आर्थिक स्थिति के सुधार में ट्रांसलेट नहीं हो सका। अपने राजनीतिक लक्ष्यों

को साधने के लिए तमाम पार्टियां मुसलमानों का वर्षों से तुष्टिकरण करते आ रही है। मगर वर्तमान सरकार द्वारा मुसलमानो को सरकार एवं पार्टी में शामिल करना, कम ब्याज दरों पर लोन उपलब्ध कराना या ट्रिपल तलाक को रद्द करने जैसे कदमों ने पहली बार मुसलमानों को आर्थिक एवं सामाजिक विकास का केंद्र बनाया है। 'पीपल रिसर्च ऑफ़ इंडिया कंस्यूमर इकॉनमी' के 2024 के रिपोर्ट के मुताबिक 2015 से 2023 के बीच भारत में मुसलमानों की औसत घरेलु आय में 27.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो हिन्दुओं (18.8 प्रतिशत) के औसत घरेलु आय से लगभग 11 प्रतिशत अधिक है। विडंबना यह है कि इन तथ्यों के बावजूद विपक्ष ने भारत के मुसलमानों को भाजपा से डराने का कोई कसार नहीं छोड़ा। यहां तक की देशहित में लिए गए सीएए (सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल) और एनआरसी (नेशनल रजिस्टर आफ सिटिजनशिप) जैसे जरुरी कदमों को मुस्लिम विरोधी के रूप में सिर्फ प्रस्तुत ही नहीं किया गया बल्कि इसे लेकर देशभर में अराजकता का माहौल बनाने की भी कोशिश हुई। मगर आज देश विपक्ष के तुष्टिकरण के रणनीति को अच्छी तरह समझ रहा है और इसके विरोध में मुखर होकर अपने भाव प्रकट कर रहा है।

क्षेत्रीय भाषा और भारतीय ज्ञान परंपरा का महत्व

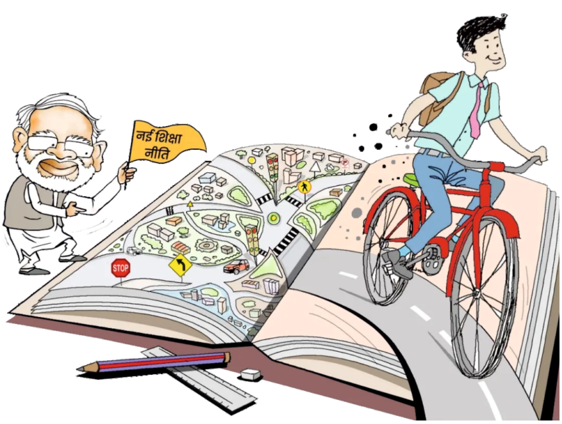

भाषा केवल संवाद का माध्यम मात्र नहीं होती बल्कि वह किसी भी समाज के पहचान को बनाये रखने, सामाजिक एकता को बढ़ावा देने, शिक्षा को सुलभ बनाने एवं नागरिक भागीदारी को सुनिश्चित करने में अहम योगदान देती है। भारत जैसे बहुभाषी देश के ऊपर किसी एक भाषा को थोपना सिर्फ अकल्याणकारी ही नहीं बल्कि अन्यायपूर्ण भी है। शोध की माने तो जो व्यक्ति अपने मातृभाषा पर अच्छी पकड़ बना लेता है, वह विश्व का कोई भी भाषा सरलता से सीख सकता है। भारत में औपनिवेशिक मानसिकता के प्रभाव के कारण वर्षो से अंग्रेजी बोलने वालों को क्षेत्रीय भाषा बोलने वालों की तुलना में अधिक इंटेलेक्चुअल समझा जाता रहा है। हलांकि वर्तमान सरकार द्वारा शिक्षा, बैंकिंग, न्यायपालिका एवं अन्य सरकारी संस्थानों में क्षेत्रीय भाषा को बढ़ावा देने के प्रयासों ने ऐसे विमर्शों को सुधार कर समाज को पहले से ज्यादा समावेशी बनाना शुरू कर दिया है। इसके अलावा नई शिक्षा निति 2020 जैसे पहल से क्षेत्रीय भाषाओं और भारतीय ज्ञान परम्पराओं का एकीकरण करना परिवर्तनकारी कदम है। इससे क्षेत्रीय भाषा बोलने वाले तमाम भारतीयों को भारत के विज्ञान, कला, दर्शन, गणित, खगोल, चिकित्सा समेत विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध शोध आधारित सामाजिक एवं बौद्धिक विरासत को आत्मसात करने का अवसर प्राप्त होगा। आज पूरा विश्व जिन आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक चुनौतियों का समाधान ढूंढ रहा है वह भारतीय ज्ञान परंपरा में निहित इंडियन मॉडल ऑफ़ डेवलपमेंट में पहले से ही मौजूद है, जरुरत है तो सिर्फ उनका पुनः अवलोकन करने का। आज विश्वविद्यालयों में शोध के क्षेत्र में भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़े विषय ट्रेंड कर रहे हैं जिनके इनसाइट्स पूरे स्कॉलरली डोमेन को भारत के ज्ञान भण्डार से बोध करा कर विस्मित कर रहा हैं। यह बदलते विमर्श का प्रत्यक्ष उदाहरण है।

नए भारत की पाकिस्तान नीति दृढ़ता, संवाद और सुरक्षा का संतुलन

भारत और पाकिस्तान, दक्षिण एशिया की भू–राजनीति के दो सबसे महत्वपूर्ण ध्रुव है। ये दोनों 1947 में विभाजन के बाद से ही एक जटिल, विरोधाभासी और तनावपूर्ण रिश्ते में बंधे रहे हैं। इस रिश्ते की पहचान ऐतिहासिक विवादों, खासकर जम्मू और कश्मीर पर गतिरोध, और पाकिस्तान की धरती से प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद के कारण आई गहरे अविश्वास से होती है। हालांकि, इक्कीसवीं सदी के तीसरे दशक में प्रवेश करते हुए, 'नए भारत' ने अपनी पाकिस्तान नीति में एक महत्वपूर्ण और निर्णायक बदलाव लाया है।

मोदी युग में भारत ने "पहले प्रतिक्रिया, फिर निर्णय" की परंपरा को तोड़ते हुए "पहले निर्णय, फिर कार्रवाई" का नया सूत्र स्थापित किया है। अब भारत आतंकवाद के हर रूप पर सिर्फ "निंदा" नहीं करता, बल्कि "प्रत्युत्तर" देता है। चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक, भारत ने स्पष्ट संदेश दिया है कि "नई दिल्ली अब चुप नहीं बैठेगी।" प्रधानमंत्री मोदी की नीति ने पाकिस्तान को यह समझा दिया है कि बातचीत अब आतंक और विश्वासघात के साए में नहीं हो सकती। कूटनीति, सुरक्षा और वैश्विक मंचों पर भारत की दृढ़ता ने दुनिया को भी यह दिखा दिया कि नया भारत न तो दबाव में झुकता है और न ही सीमाओं की रक्षा में समझौता करता है।

दरअसल भारत ने दशकों तक, अपनी नीति को 'रणनीतिक संयम' पर आधारित रखा। इसका उद्देश्य परमाणु युद्ध के खतरे के बीच सैन्य टकराव से बचना और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को कूटनीतिक रूप से अलग–थलग करना था। हालांकि, 2008 के मुंबई हमलों के बाद से यह सोच बदलने लगी। उरी (2016) और पुलवामा (2019) जैसे बड़े आतंकी हमलों ने नई दिल्ली को यह मानने पर मजबूर कर दिया कि केवल कूटनीतिक विरोध और संयम पाकिस्तान के छद्म युद्ध (Proxy War) को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।

'नया भारत' अब एक 'नए सामान्य' (New Normal) की ओर बढ़ गया है, जहाँ आतंकवाद के खिलाफ दंडात्मक सैन्य कार्रवाई को एक राजनीतिक–सैन्य विकल्प के रूप में शामिल किया गया है। यह वह धुरी है जिस पर 'नए भारत' की पाकिस्तान नीति टिकी है, जिसके तीन प्रमुख स्तंभ हैं–

दृढ़ता–आतंकवाद के खिलाफ शून्य सहिष्णुता

मोदी युग में भारत की नीति का सबसे मूलभूत सिद्धांत आतंकवाद के खिलाफ 'शून्य सहिष्णुता' है। इसका सीधा संदेश है– आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते। भारत ने स्पष्ट रूप से यह शर्त रखी है कि किसी भी सार्थक द्विपक्षीय बातचीत के लिए पाकिस्तान को अपनी धरती से पनप रहे आतंकवादी बुनियादी ढांचे पर ठोस, अपरिवर्तनीय और सत्यापन योग्य कार्रवाई करनी होगी।

इस दृढ़ता का सबसे मुखर प्रदर्शन बालाकोट एयर स्ट्राइक (2019) और भारत के 'नए सैन्य सिद्धांत' में निहित है। बालाकोट ने दशकों पुराने 'रणनीतिक संयम' को तोड़ते हुए दिखाया कि भारत सीमा पार जाकर भी आतंकवाद के ठिकानों को निशाना बनाने में संकोच नहीं करेगा। भारत ने 'ऑपरेशन सिंदूर' जैसे कदम उठाकर यह संदेश दिया है कि पाकिस्तान द्वारा पारंपरिक या उप–पारंपरिक किसी भी तरह के उल्लंघन का जवाब अब सीमा के भीतर सैन्य या खुफिया साधनों से दिया जाएगा।

कूटनीतिक मोर्चे पर, भारत ने पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सफलतापूर्वक अलग–थलग किया है, जिससे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) जैसे निकायों में उस पर दबाव बढ़ा है। इस दृढ़ता का एक अन्य आयाम यह भी है कि भारत ने जम्मू और कश्मीर से जुड़े अपने आंतरिक मामलों में किसी भी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है, जिसमें पाकिस्तान का कश्मीर पर निरंतर राजनीतिक और राजनयिक अभियान शामिल है।

संवाद – शर्तों पर आधारित खुलापन

दृढ़ता की नीति का मतलब यह कतई नहीं है कि संवाद के दरवाजे स्थायी रूप से बंद कर दिए गए हैं। भारत एक जिम्मेदार शक्ति के रूप में शांति और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वह यथार्थवादी शर्तों पर आधारित संवाद की बात करता है। यह नीति 'शर्तों के अधीन संवाद' के सिद्धांत पर चलती है।

भारत और पकिस्तान ने 2021 में, दोनों देशों के सैन्य संचालन महानिदेशकों (DGsMO) द्वारा नियंत्रण रेखा (LoC) पर संघर्ष विराम समझौते को बहाल करने पर सहमति व्यक्त की। यह कदम दोनों देशों के बीच तनाव कम करने और क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने की पारस्परिक इच्छा को दर्शाता है। हालाँकि, भारत ने इसे 'शांति' की शुरुआत नहीं, बल्कि तनाव कम करने की दिशा में एक 'व्यावहारिक कदम' माना है।

भारत और पाकिस्तान शंघाई सहयोग संगठन (SCO) और सार्क (SAARC) जैसे बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग करते रहे हैं, जो उन्हें द्विपक्षीय तनाव से परे अनौपचारिक बातचीत और क्षेत्रीय मुद्दों पर सहयोग के लिए एक तटस्थ मंच प्रदान करता है। भारत का स्पष्ट रुख यह है कि जब भी पाकिस्तान आतंकवाद के समर्थन को पूरी तरह से त्याग देगा और विश्वास बहाली के ठोस कदम उठाएगा, भारत हमेशा बातचीत के लिए तैयार रहेगा, लेकिन बातचीत राष्ट्रीय हितों और संप्रभुता की कीमत पर नहीं होगी।

सुरक्षा – राष्ट्रीय हितों का अभेद्य कवच

- तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोपरि रखना है। यह केवल सीमा सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि एक व्यापक सुरक्षा रणनीति है जो भू–रणनीतिक वास्तविकताओं पर आधारित है।
- पाकिस्तान के परमाणु शस्त्रागार और चीन के साथ उसके गहरे सैन्य गठबंधन (CPEC और अन्य रक्षा सहयोग) को देखते हुए, भारत अपनी पारंपरिक सैन्य क्षमताओं और खुफिया तंत्र के आधुनिकीकरण में तेजी ला रहा है। यह एक निवारक क्षमता बनाए रखने के लिए आवश्यक है।
- सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ावा देने और आंतरिक सुरक्षा को अस्थिर करने के प्रयासों का मुकाबला करने के लिए, भारत ने अपनी सीमा सुरक्षा (बीएसएफ, सेना) और आंतरिक सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित किया है।
- भारत अपनी सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए वैश्विक साझेदारों, विशेषकर खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) के सदस्यों और अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी मजबूत कर रहा है, ताकि सऊदी–पाकिस्तान धुरी के किसी भी भू–राजनीतिक प्रभाव का संतुलन बनाया जा सके।
- इसका यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि

मोदी युग में 'नए भारत' की पाकिस्तान नीति एक यथार्थवादी और दूरदर्शी रणनीति है, जो अतीत के भावनात्मक दृष्टिकोण से परे है। यह नीति इस कटु सत्य को स्वीकार करती है कि एक अस्थिर, परमाणु हथियारों से लैस और आतंकवाद प्रायोजित करने वाला पड़ोसी भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। यह नीति सफलतापूर्वक दृढ़ता, संवाद और सुरक्षा के बीच एक नाजुक संतुलन स्थापित करती है। दृढ़ता आतंकवाद को अस्वीकार करती है, संवाद शर्तों पर आधारित शांति की गुंजाइश छोड़ता है और सुरक्षा राष्ट्रीय हितों को अभेद्य कवच प्रदान करती है। यह दृष्टिकोण केवल भारत–पाकिस्तान संबंधों के लिए ही नहीं, बल्कि संपूर्ण दक्षिण एशिया की स्थिरता के लिए एक नया और मजबूत आधार प्रदान करता है, जहां पाकिस्तान को भी अंततः यह चुनना होगा कि वह आतंक और अस्थिरता का केंद्र बनना चाहता है या क्षेत्रीय विकास और शांति का भागीदार।

राणा सांगा एक महान योद्धा

- महाराणा सांगा अर्थात महाराणा संग्राम सिंह। इस महान योद्धा के बारे में आप जितना पढ़ेंगे, उतना ही आश्चर्य में डूबते चले जायेंगे। लगभग सौ युद्ध और अधिकांश में विजय! शरीर के हर अंग पर युद्ध के चिन्ह सजाए इस रणकेसरी को खंडहर, सैनिकों का भग्नावशेष आदि कहा गया है ३ जैसे रणचंडी ने उन्हें अपने हाथों से पुरस्कार स्वरूप घावों के आभूषण पहनाए हो।

एक योद्धा की एक आँख चली गयी..किसी दूसरे युद्ध में एक पैर नाकाम हो गया, वह फिर भी लड़ता रहा। किसी युद्ध में एक हाथ कट गया, वह फिर भी उसी उत्साह के साथ लड़ता रहा३ जैसे युद्ध युद्ध नहीं, उसकी पूजा हो, तपस्या हो३! ऐसी अद्भुत गाथाएं भारत में ही मिलती हैं३। कुछ योद्धाओं की भूख प्यास युद्ध से ही तृप्त होती है। उन्हें न शरीर के घाव विचलित करते हैं, न परिस्थितियों की विकरालता रोक पाती है। युद्ध उनके लिए आनन्द का उत्सव होता है। समुद्रगुप्त, मिहिरभोज आदि की तरह राणा सांगा भी वैसे ही योद्धा थे।

अधिकांश लोग महाराणा सांगा को बाबर से मिली पराजय के लिए जानते हैं। वामपंथी जिहादी इतिहासकार उन्हें लूटेरे बाबर को भारत पर आक्रमण केलिए आमंत्रित करने में पंजाब के शासक दौलत खां लोदी के बराबर जिम्मेदार बताते हैं। यह वस्तुतः भारत की वामपंथी शिक्षा व्यवस्था का दिवालियापन है। राणा सांगा खुद दिल्ली के सुल्तान इब्राहीम लोदी को दो दो बार हरा चुके थे, उन्हें किसी बाहरी लूटेरे के सहयोग की क्या आवश्यकता थी?

इब्राहीम लोदी का रिश्तेदार दौलत खां लोदी दिल्ली की सत्ता पाना चाहता था इसलिए उसने लूटेरे बाबर को आमंत्रित किया था और इसके लिए उसने राणा सांगा से सहायता माँगा था और राणा ने दौलत खां लोदी और बाबर को सहयोग का वचन दिया था। पर जब राणा सांगा ने बाबर को खुद ही दिल्ली पर अधिकार कर सत्ता हथियाने केलिए अग्रसर देखा तो उन्होंने उसकी कोई सहायता नहीं की बल्कि भारत की भूमि से उस लूटेरे, आक्रमणकारी को भगाने केलिए हिन्दु राजाओं और मुस्लिम शासकों के सहयोग से विशाल सेना संगठित किया और बाबर से युद्ध किया।

वास्तव में महाराणा सांगा को याद किया जाना चाहिये दिल्ली सल्तनत के इब्राहिम लोदी को दो दो बार हराने के लिए, गुजरात सल्तनत वाले मुजफ्फर शाह को पराजित करने के लिए। उन्हें याद किया जाना चाहिये मालवा के शासक महमूद खिलजी को पराजित कर तीन महीने तक बांध कर रखने के लिए३मालवा से जजिया समाप्त करने के

लिए, बयाना के युद्ध में बाबर को पराजित करने के लिए। उन्हें याद किया जाना चाहिये बर्बर आतंकियों के विरुद्ध भारतीय शक्तियों का एक मजबूत संघ बनाने के लिए आदि।

मेवाड़ के राणा सांगा ने मुस्लिम सेनापति की बेटी मेरूनीसा से शादी की. इसके अलावा उन्होंने तीन और मुस्लिम लड़कियों से शादी की थी. अपराजित योद्धा के तौर पर पहचाने जाने वाले महाराणा कुंभा ने भी जागीरदार वजीर खां की बेटी से शादी की थी.

महाराणा सांगा की मृत्यु की कहानी भी अद्भुत ही है। कहते हैं कि उन्हें उनके सामंतों ने ही विष दे दिया। क्यों? क्योंकि खानवा के युद्ध में बाबर से पराजित होने के तुरंत बाद ही उन्होंने पुनः युद्ध की तैयारी शुरू कर दी थी। वह भी तब, जब उनका शरीर पूरी तरह से जर्जर हो चुका था। बुरी तरह घायल होने और सेना और सहयोगियों का समर्थन खो देने के बाद भी युद्ध में उतर जाने का साहस युगों में किसी एक के भीतर होता है। किसी योद्धा को रोकने के लिए उसके प्रिय लोगों को ही उसे विष देना पड़े, तो आप राष्ट्र के प्रति उसकी भावनाओं का अंदाजा लगा सकते हैं।

योद्धा का आकलन उसकी राजनैतिकध्कूटनीतिक विजयों पराजयों से कम, उसके शौर्य से अधिक होना चाहिए। उसमें राष्ट्र के लिए लड़ने रहने का जुनून कितना है। कोई भी राष्ट्र किसी एक युद्ध में हार जाने से समाप्त नहीं होता, राष्ट्र पराजित होता है जब उसके नायकों का शौर्य चूक जाता है। हजार वर्षों के संघर्ष की यात्रा में भारत अनेक युद्ध हारा है, पर उसके उसके नायकों का शौर्य, संघर्ष और राष्ट्र के प्रति निष्ठां कभी पराजित नहीं हुआ। यही कारण है कि भारत हार कर भी जिन्दा है वर्ना दर्जनों राष्ट्र इतिहास में अपना अस्तित्व खो चुके हैं। आईये विस्तार से इस महायोद्धा की गाथा पढ़ें।

अपने पराक्रम के लिए प्रसिद्ध मेवाड़ के राणा सांगा 1508 में मेवाड़ के उस सिंहासन पर बैठे, जिसे कभी प्रतापी महाराणा कुम्भा ने सुशोभित किया था और जिन्होंने मालवा के सुलतान को परास्त किया था। ये वही महाराणा कुम्भा थे, जिनकी यशोगाथा की साक्षी कुंभलमेर के विशाल किले की प्राचीरें रही हैं।

राणा सांगा ने भारतीय इतिहास के अत्यंत गंभीर अवसर पर इतिहास के रंगमंच पर क़दम रखा था। उन्हें हिंदूपत, अर्थात हिंदुओं का प्रमुख कहा जाता था। जब सोलहवीं सदी के शुरुआती दशकों में दिल्ली के अफगान सुल्तान कमजोर हो रहे थे, राजपूताना में राणा सांगा के नेतृत्व में हिंदू राजाओं का एक विशाल संगठन उभर रहा था, जो दिल्ली में अफगान सत्ता को ख़त्म करके हिंदुओं की सत्ता की स्थापना करना चाहता था। देशभक्ति, कर्तव्यनिष्ठा, उदारता और शौर्य जैसे गुणों के लिए और साथ ही एक शक्तिशाली मेवाड़ रियासत के प्रमुख के रूप में भारत में राणा सांगा की अलग ही प्रतिष्ठा थी। वे मेवाड़ के सबसे महान महाराणा थे। उनके शासनकाल में मेवाड़ राज्य शक्ति और समृद्धि के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गया था। उन्हें मेवाड़ की प्रतिष्ठा का कलश माना जाता था। राणा सांगा अदम्य साहसी थे। एक भुजा, एक टांग और एक आंख खोने और कई जख्म खाने के बावजूद वे महान पराक्रमी थे।

महाराणा सांगा ने सिकंदर लोदी के समय ही दिल्ली के अधीनस्थ इलाकों पर अधिकार करना शुरू कर दिया था। सिकंदर लोदी के उत्तराधिकारी इब्राहिम लोदी ने 1517 में मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया था। खातोली(कोटा) नामक स्थान पर दोनों पक्षों के बीच युद्ध हुआ जिसमें महाराणा सांगा की विजय हुई। इस युद्ध में तलवार से सांगा का बायाँ हाथ कट गया था और घुटने पर तीर लगने से वह हमेशा के लिए लंगड़े हो गए थे। खातोली की पराजय का बदला लेने के लिए 1518 में इब्राहिम लोदी ने मियां माखन की अध्यक्षता में महाराणा सांगा के विरुद्ध एक बड़ी सेना भेजी परन्तु हार का सामना करना पड़ा।

इन विजयों के परिणामस्वरूप राणा संग्रामसिंह के राज्य की सीमा आगरा के पास तक पहुंच गई। इब्राहीम लोदी का मानमर्दन करने से राणा सांगा

की विजय गाथा की चर्चा सारे उत्तरी भारत में हुई। लेकिन यह गाथा यहीं ख़त्म नहीं हुई। सन 1519 में सुल्तान महमूद मेदिनीराय पर आक्रमण के लिए रवाना हुआ था। इस बात की खबर लगते ही सांगा भी एक बड़ी सेना के साथ गागरोन पहुंच गए। यहां हुई लड़ाई में सुल्तान की बुरी तरह से पराजय हुई। सुल्तान का पुत्र आसफखाँ इस युद्ध में मारा गया तथा वह स्वयं घायल हुआ। महाराणा सांगा सुल्तान को अपने साथ चित्तौड़ ले गए, जहां सांगा ने उसे 3 माह कैद में रखा था।

इस युद्ध में विजय प्राप्त करने से चंदेरी के क़िले के अलावा मालवा के अधिकांश हिस्सों पर राणा का क़ब्जा हो गया। मालवा में अपनी सत्ता स्थापित करने के बाद राणा सांगा ने मेदिनी राय को हिंदुओं पर लगाए जा रहे जज़िया कर को ख़त्म करने का आदेश दिया। राजपूताने पर एकछत्र राणा सांगा ने अपने राजनीतिक कौशल और सैन्य प्रतिभा से सभी राजपूत राज्यों को संगठित किया और उन्हें एक छतरी के नीचे ले आए। उन्होंने अपना प्रभुत्व उत्तर में सतलज नदी से दक्षिण में नर्मदा नदी तक और पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में बयाना, भरतपुर तक विस्तृत कर लिया था। इस प्रकार उस जमाने में भारत में उनका हिंदू साम्राज्य काफी विस्तृत था। इतने बड़े इलाक़े में राणा सांगा के अलावा एक ही हिंदू राज्य था, दक्षिण का विजयनगर साम्राज्य जो गोदावरी से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ था।

बाबर अपने संस्मरण 'बाबरनामा' में राणा सांगा को सबसे शक्तिशाली शासक बताता है जिसने अपनी तलवार के बल पर ऊंचा स्थान हासिल किया था। कर्नल टाड के अनुसार, उनके पास 80 हजार घोड़े, ऊंचे दर्जे के सात राजा, 9 राव और 104 रावल थे। 500 हाथी उनकी सेना में थे। मारवाड़ और आम्बेर उन्हें सम्मान देते थे और ग्वालियर, अजमेर, सीकरी (वही जो अब फतेहपुर सिकड़ी कहलाता है और जिनकी नगरी को वामपंथी जिहादी इतिहासकार अकबर द्वारा बसाया बताते है), रायसेन, कालपी, चंदेरी, बूंदी, गागरौन, रामपुरा और आबू के राजा उन्हें अपना अधिपति मानते थे।

बाबर ने अपनी कम सेना के बावजूद पानीपत के युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहीम लोदी की विशाल सेना को पराजित किया और दिल्ली–आगरा पर क़ब्जा कर लिया था। राणा सांगा जैसे वीर और महत्वाकांक्षी योद्धा ने इस विदेशी आक्रांता को देश के बाहर निकालने का संकल्प किया और सभी राजपूतों के सहयोग से एक शक्तिशाली सेना जुटाई।

राणा ने बयाना पर आक्रमण किया और वहां के गवर्नर मेहदी ख़्वाजा को हराकर बयाना के क़िले में बंद रहने के लिए मजबूर कर दिया। राणा के साथ बहुत–से शक्तिशाली सरदार हो लिए, जिनमें रायसेन का सिलहदी, हसन ख़ां मेवाती और इब्राहीम लोदी का भाई महमूद लोदी भी था। राणा ने मान लिया कि बाबर पर विजय हासिल करने के बाद महमूद लोदी को चितौड़ के प्रतिनिधि के रूप में दिल्ली का सिंहासन सौंप दिया जाएगा। अब बाबर ने एक सैनिक टुकड़ी बयाना की सहायता के लिए भेजी, लेकिन वहां के दुर्ग रक्षकों से मुठभेड़ में बाबर की सेना क़ामयाब न हो सकी और घबराकर भाग खड़ी हुई।

एक निर्णायक संघर्ष खानवा में दोनों सेनाएं एक–दूसरे के सामने थीं। 16 मार्च 1527 को प्रातः 9 बजे लड़ाई शुरू हुई। राजपूतों के लिए मुगलों का तोपख़ाना भयंकर सिद्ध हुआ। 20 घंटे चले इस भयानक युद्ध में बाबर विजयी हुआ। राणा सांगा घायल हो गए और उनके अनुगामी उन्हें बसवा नामक सुरक्षित स्थान पर ले गए। राणा सांगा के सहयोगी हसन मेवाती और अन्य प्रमुख सरदार वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन महमूद लोदी साफ बचकर निकल गया।

डाक टिकट

पता